

दिनांक 05 जुलाई, 2019 को प्रातः 11:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा बड़े पर्दे पर बजट का लाइव प्रसारण डॉ गौर हरी सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर में आयोजन किया गया । बजट सत्र की समाप्ति के पश्चात समय अपराह्न 01:00 बजे प्रेस-वार्ता का आयोजन किया गया । मर्चेट्स चैम्बर की ओर से मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.एम.गर्ग, डॉ. आई.एम. रोहतगी, श्री पदम् कुमार जैन, श्री संतोष कुमार अग्रवाल, श्री सुधींद्र कुमार जैन, श्री मुकुल टंडन, श्री शरद शाह, व् चैम्बर के सचिव श्री महेंद्र नाथ मोदी द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गयी:

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया जो एक विज्ञ-डॉक्यूमेंट से परिपूर्ण था । मोदी सरकार फेज-2 में प्रस्तुत यह बजट भारत की दूरदर्शी प्रगति को दर्शाता है । भारत सरकार ने अपने मोटो Peform, Reform, Transform को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट प्रस्तुत किया । सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए सरकार ने क्या सोच रखा है और क्या कदम उठाना जरूरी है, इसका रोडमैप देते हुए वित्त मंत्री ने रूरल इंडिया, यूथ ऑफ इंडिया, इज ऑफ लिविंग, वीमेन वेलफेयर, बैंकिंग और फाइनेंसियल सेक्टर तथा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट कर के क्षेत्र में बजट के माध्यम से साहसिक व् सराहनीय कदम उठाया है । जो निश्चित तौर पर अगर क्रियान्वित होता है तो देश की अर्थव्यवस्था को एक नयी गति प्रदान करेगी ।

बजट में प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव विशेष तौर पर सराहनीय है:

- इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन के लिए 10000 करोड़ का आवंटन किया गया ।
- 1 नेशन 1 ग्रिड के तहत बिजली वितरण व्यवस्था का प्रावधान किया गया ।
- छोटे और माध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए पेंशन योजना प्रस्तावित की गयी ।
- एविएशन इंश्योरेन्स मीडिया क्षेत्र में FDI को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया ।
- 1.95 करोड़ मकान निम्न वर्ग को 2022 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया ।
- 1.25 लाख किलोमीटर सड़क ग्रामीण योजना के तहत बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया ।
- 70000 करोड़ का कैपिटल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए उपयोग किया जाएगा जिससे मार्केट में मुद्रा साख (क्रडिट फ्लो) बढ़ेगा ।
- अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स योजना के अंतर्गत रुपया 45 लाख तक के लोन की ब्याज अदायगी पर 1.5 लाख अतिरिक्त कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया गया ।
- बैंक खाते से वार्षिक 1 करोड़ रुपया से अधिक कैश निकालने पर 2% राशि TDS लगाने का प्रावधान किया गया ।
- 1.05 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में विनिवेश किया जाना प्रस्तावित किया गया ।

धन्यवाद